दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार, 22 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 203

महत्वपूर्ण एवं खास

जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर

0 सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 2 हफ्ते टली

नईदिल्ली (आरएनएस)। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दो हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। हालांकि, तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है, तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है। वहीं अदालत ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। अगर तब तक निगम ने जहांगीरपुरी में कोई कार्रवाई की तो उसे अदालत गंभीरता से लेगी और इससे अवमानना माना जाएगा।

मुंबई के खार इलाके में सात मंजिला इमारत में लगी आग

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई के उपनगर खार में बृहस्पतिवार सुबह सात मंजिला इमारत में आग लग गई। एक नगर निगम अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। आग सुबह करीब 11 बजे खार (पश्चिम) में गुरु गंगेश्वर मार्ग स्थित नोथन विला इमारत की चौथी मंजिल पर बने एक फ्लैट में लगी। अधिकारी ने बताया कि दमकल की कम से कम आठ गाडिय़ां, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और अन्य अग्निशमन के उपकरण मौके पर भेजे गए और आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

12.06 करोड़ रुपए की कस्टम चोरी में चना कारोबारी रजत सारडा गिरफ्तार

इंदौर (आरएनएस)। रजत एग्रो कमोडिटी प्रा.लि. के कर्ताधर्ता रजत पिता गोपालदास सारडा को कस्टम कमिश्नरेट इंदौर और मुंबई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल इंटेलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (एक्सपोर्ट) की छानबीन में काबुली चने के इमपोर्ट और एक्सपोर्ट में 12.06 करोड़ की टैक्स चोरी की पुष्टि हुई है। रजत के खिलाफ मुंबई में कस भी दर्ज है इसीलिए मुंबई ले जाने के लिए कोर्ट ने तीन दिन को ट्रांजिट रिमांड दी है। रजत सारडा को ही चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट इंदौर लोकेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट में कस्टम डिपार्टमेंट की पेरवी एडवोकेट चंदन ऐरन ने की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कस्टम डिपार्टमेंट की स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (एक्सपोर्ट) के अधीक्षक बिगन कुमार की ओर से सारडा के खिलाफ कस्टम एक्ट में केस दर्ज किया था। इस केस की डायरी इंदौर विंग को सौंपी गई। डायरी पर्याप्त साक्ष्यों और 31 जनवरी 2020 को धारा 108 में रिकार्ड कबूलनामे के आधार पर सारडा की गिरफ्तार किया गया। रजत ने स्वीकारा कि उसने काबूली चने के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में टैकस चोरी की। बहरहाल कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले सारडा को मेडिकल चेकअप कराया गया। रजत को मुंबई पेश करना है जो इंदौर से 600 किमी दूर है। इसीलिए कोर्ट ने 21 अप्रैल तक की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दी। इंदौर के काबुली चना एक्सपोर्टर ने किस तरह रशियन चने को प्रोससिंग के नाम पर इम्पोर्ट किया और कैसे उसकी जगह हल्की ग्रेड के चने को एक्सपोर्ट कर दिया। मामले में ईडी और विदेश व्यापार विभाग को इसकी शिकायत की गई थी। जनवरी 2020 में मामले में मुंबई कस्टम विभाग की टीम इंदौर पहुंची और रजत सारडा की फर्म रजत एंटरप्राइजेज सहित करीब दस फर्मों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। रजत सारडा के खिलाफ 23 जनवरी 2020 को सर्च हुई थी। 31 जनवरी को बयान दर्ज हुए। फरवरी में पहला समन जारी हुआ रजत उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद दो मार्च 2022 तक 14 समन जारी हुए जिनमें रजत ने उपस्थिति होना मुनासिब नहीं समझा इसीलिए मुंबई विंग के साथ मिलकर पहले रजत को कस्टम कमिश्नरेट इंदौर बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार किया गया।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ को आरओबी के लिए 700 करोड़ रूपए देने की घोषणा

छत्तीसगढ़ में 9240 करोड़ रूपए लागत की 33 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास

रायगढ़-घरघोड़ा-धरमजयगढ़-पत्थलगांव मार्ग, अंबिकापुर-वाड्रफनगर-बम्हनी-रेनकूट-बनारस मार्ग, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को केन्द्रीय मंत्री ने भारत माला परियोजना-2 में स्वीकृति का दिया आश्वासन

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज छत्तीसगढ़ में 9240 करोड़ रूपए लागत की कुल 1017 किलोमीटर लम्बाई की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। यह समारोह राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया।

इन सड़कों के बनने से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के लिए सुचारू रोड नेटवर्क विकसित होगा। इससे ईंधन, यात्रा समय, दूरी और कुल परिवहन लागत में बचत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह में केन्द्रीय मंत्री गडकरी से छत्तीसगढ़ की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति देने का आग्रह किया। जिस पर गडकरी ने अधिकांश परियोजनाओं को स्वीकृति देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजनाओं को सहृदयता पूर्वक स्वीकृति प्रदान करने के लिए नितिन गडकरी के प्रति आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के तीन मार्गो- रायगढ़-घरघोड़ा-धरमजयगढ़- पत्थल गांव मार्ग, लंबाई 75 किलोमीटर, अंबिकापुर-वाड्रफनगर-बम्हनी-रेनकूट-बनारस मार्ग, लंबाई 110.60 किलोमीटर, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग, लंबाई 37 किलोमीटर को भारत माला परियोजना के तहत स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया, जिस पर केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने इन सड़कों को भारत माला परियोजना-2 में शामिल करने का आश्वासन दिया।

बघेल ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर जन सामान्य को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, रायपुर से धमतरी फोरलेन का निर्माण कार्य के तहत राज्य सरकार द्वारा पूर्ण किए गए। रायपुर से शदाणी दरबार तक 10 किलोमीटर हिस्से में सर्विस रोड की स्वीकृति प्रदान करने, रायपुर शहर में टाटीबंध चौक से मैगनेटो मॉल के बीच फ्लाई ओवर निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में ग्राम धनेली से विधानसभा, बलौदाबाजार होते हुए सारंगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग को एन.एच.53 से जोड़ने तथा विधानसभा से जोरा (एन.एच.53) के इस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे बिलासपुर से नवा रायपुर, महासमुंद, संबलपुर की ओर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध हो जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने राम वन गमन पथ लंबाई 1000 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने, चंद्रपुर-खरसिया-पत्थलगांव मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने, कुम्हारी-भिलाई बायपास लंबाई 23 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग, बरदुला-नगरी-कांकेर-संबलपुर-मानपुर मार्ग, लंबाई 195 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3525 किलोमीटर है। इसमें से 2447 किलोमीटर का लोक निर्माण विभाग तथा 1078 किलोमीटर का एन.एच.ए.आई द्वारा संधारण एवं निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने चांपा-उरगा-कोरबा मार्ग निर्माण, पाली-कटघोरा मार्ग निर्माण, मुंगेली-पोण्डी मार्ग, झलमला-शेरपार-मानपुर मार्ग, अभनपुर-पोण्ड मार्ग, मदांगमुड़ा से देवभोग मार्ग के निर्माण की स्वीकृति देने तथा भारत माला एवं इकोनोमिक कॉरीडोर योजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम मार्ग, बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग, चांपा-कोरबा मार्ग को शामिल करने पर केन्द्रीय मंत्री गडकरी को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में राज्य सरकार का मुख्यतः भू-अर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन, यूटिलिटि शिफ्टिंग के कार्यों का दायित्व रहता है, इन सभी कार्यों को समय से पूरा कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित की गई है, जिसके द्वारा हर महीने कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जाती है। ताकि एन.एच. की परियोजनाएं समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2022-23 के एनुवल प्लान में राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 2100 करोड़ रुपए का एनुवल प्लान प्रस्तुत किया गया है।

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। अच्छी सड़के किसी भी देश और राज्य की समृद्धि और सम्पन्नता का आधार होती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह पर छत्तीसगढ़ में आरओबी निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये देने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके अतिरिक्त आरओबी के लिए वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ को 400 करोड़ रुपये देंगे। इस तरह छत्तीसगढ़ में आरओबी के लिए कुल 700 करोड़ रूपए मिलेंगे। उन्होंने बताया कि आरंग पचेरा के पास 200 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आयरन और सीमेंट के 118 उद्योग हैं। लॉजिस्टिक सुविधा विकसित होने से उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने एन.एच. के करीब लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपने विभाग की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि यदि एन.एच. की स्वीकृत और निर्माणाधीन विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन और वन क्षेत्रों में अनुमति देने का काम शीघ्रता से किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 तक लगभग एक लाख करोड़ रूपए की सड़कों का निर्माण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने एथेनॉल के पंप खोलने की अनुमति दी है। एथेनॉल भविष्य का फ्यूल है। छत्तीसगढ़ में चावल और पैरे से ऐथॉनाल उत्पादन की अच्छी संभावना है। एथेनॉल का उत्पादन होने से किसान अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बनेगा। गडकरी ने रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत माला परियोजना इकोनॉमिक कारीडोर योजना के तहत स्वीकृत इस सड़क परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आने वाले समय में यह मार्ग छत्तीसगढ़ के विकास का पथ साबित होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 16 हजार करोड़ रूपए की लागत की इस परियोजना से रायपुर-विशाखापट्टनम के बीच 200 किलोमीटर कम होगी। इस सड़क के बनने से छत्तीसगढ़ की एक अच्छे बंदरगाह से कनेक्टीविटी हो सकेगी और छत्तीसगढ़ का खनिज देश-दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सुगमतापूर्वक पहुंच सकेगा। गडकरी ने छत्तीसगढ़ की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी समारोह में दी।

समारोह को छत्तीसगढ़ के गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद सर्वश्री सुनिल सोनी, संतोष पाण्डेय और अरूण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित अनेक विधायक और जनप्रतिनिधि तथा प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने स्वागत भाषण दिया।

कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे में एनआईए की महत्वपूर्ण भूमिका: शाह

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे में महत्वपूर्ण योगदान देकर केंद्र की मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की लक्ष्य सिद्धि को पूरा करने में सहयोग किया है ।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एनआईए को किसी भी तरह की ओर कोई भी मदद देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने गुरुवार को यहां एनआईए के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के जड़ से सफाये के लिए वहां टेरर फंडिंग पर प्रहार जरूरी था और एनआईए ने यह भूमिका भली-भांति निभाई है। एजेंसी ने टेरर फंडिंग के 105 मामले दर्ज किए हैं और उनसे आतंकवाद पर नकेल लगाने में सफलता मिली है।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत का हर क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ा है और पर्यावरण से लेकर आर्थिक क्षेत्र तथा आतंकवाद से निपटने में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को बेहद मजबूत बनाए जाने की जरूरत है और इसके लिए एनआईए जैसी एजेंसी को संकल्प लेकर लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप बनाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, इसे भी पुख्ता आंतरिक सुरक्षा के बल पर ही हासिल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि एनआईए ने 13 वर्ष के अपने छोटे से कार्यकाल में आदर्श मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए 93.25 प्रतिशत की दोष सिद्धि दर हासिल की है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि अब एनआईए को अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए और इसके लिए उसे एक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सूचना तथा अन्य पहलुओं को संस्थागत रूप देना होगा। उन्होंने कहा कि एनआईए देश भर की जांच एजेंसियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, इसलिए उसे सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाकर राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की तरफ बढऩा चाहिए।

शाह ने कहा कि आतंकवाद दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है और उनका मानना है कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि आतंकवाद का खात्मा और मानवाधिकारों की रक्षा परस्पर विरोधाभासी नहीं है। आतंकवाद का खात्मा कर मानवाधिकारों की रक्षा व्यापक स्तर पर की जा सकती है।

उन्होंने एनआईए से अपनी जांच पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने का आह्वान करते हुए कहा कि अब थर्ड डिग्री के बजाय जांच की पद्धति तकनीक और सूचना पर आधारित होनी चाहिए और इसकी मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस भी बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर एनआईए के महानिदेशक कुलदीप सिंह तथा गृह मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

बारामूला मुठभेड़ : लश्कर आतंकवादी ढेर, तीन सैनिक घायल

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष कमांडर मारा गया जबकि तीन जवान घायल हो गये।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक(आईजीपी) विजय कुमार ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर यूसुफ कांतरू बारामूला मुठभेड़ में मारा गया और यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है।

पुलिस के एक ट्वीट में आईजीपी के हवाले से कहा गया, ..वह जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसपीओ और उसके भाई, एक सैनिक और एक नागरिक की हाल ही में बडगाम जिले में हत्या सहित कई नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्याओं में शामिल था। पुलिस ने बताया कि बारामूला के मालवाह गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की घेराबंदी की, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती मुठभेड़ में तीन जवान घायल हो गये। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। उन्होंने बताया कि अभियान अभी जारी है। गौरतलब है कि जिले में एक स्वतंत्र सरपंच के मारे जाने के कुछ ही दिनों बाद बारामूला गांव में मुठभेड़ हुई है।

दो दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन

0-पीएम मोदी से अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

अहमदाबाद (आरएनएस)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने गुरुवार सुबह 08:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एयरपोर्ट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत किया। यहां वह एक बुलडोजर बनाने वाली कंपनी का भी दौरा करेंगे।

रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जारी हमलों के बीच जॉनसन का यह दौरा अपने आप में काफी अहम हो जाता है। खासकर ऐसे समय जब अमेरिका, ब्रिटेन के साथ यूरोपीय देश भी भारत से रूस के साथ व्यापार न करने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में जॉनसन के इस दौरे की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जॉनसन इस दौरे में भारत को रूस से हथियार या तेल खरीद कम करने को लेकर किसी तरह का भाषण नहीं देंगे। हालांकि, वे मोदी सरकार को रूसी उत्पादों के विकल्पों को लेकर प्रस्ताव जरूर दे सकते हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के क्या मायने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात में किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आखिर दोनों नेता किस तरह व्यापार समझौते से लेकर रूसी उत्पादों के विकल्प को लेकर अहम चर्चा कर सकते हैं।

बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच बातचीत का केंद्रीय मुद्दा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होगा। इसके अलावा दोनों नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। बताया गया है कि मोदी और जॉनसन जलवायु परिवर्तन को लेकर भी समझौते पर पहुंच सकते हैं। शिक्षा-नौकरियों के अलावा निवेश को लेकर भी ब्रिटिश पीएम की तरफ से बड़ा एलान आ सकता है।

रूस-यूक्रेन के युद्ध के बीच पश्चिमी देश लगातार भारत से अपील करते रहे हैं कि वह रूस से व्यापार संबंधों को तोड़े और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार्रवाई की निंदा करे। इसके अलावा हालांकि, भारत ने अब तक अपना स्थिर रुख बरकरार रखा है। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह रूस से अपने सालों पुराने रिश्तों को यूरोप के गुस्से की वजह से दांव पर नहीं लगा सकता। मौजूदा समय में भारत की तीनों सेनाएं और हथियार उद्योग रूस पर 50-60 फीसदी तक निर्भर है। इसके अलावा तेल को लेकर भी भारत कुछ हद तक रूस पर निर्भर है। ऐसे में जॉनसन इन दोनों क्षेत्रों में रूस को भारत के साझेदार के तौर पर हटाने के लिए बातचीत कर सकता है।

हालांकि, इस क्षेत्र में भी ब्रिटेन की मुसीबतें काफी ज्यादा हैं। दरअसल, भारत सरकार पहले ही साफ कर चुका है कि वह आने वाले समय में किसी भी देश से आयात बढ़ाने के बजाय मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन पर ही जोर देगा। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत को लुभाने के लिए साझा परियोजनाओं पर समझौता कर सकते हैं।

बोरिस जॉनसन और मोदी की मुलाकात का मुख्य मुद्दा सुरक्षा ही रहने वाला है। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रूस से व्यापार के मुद्दे पर भी जोर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि, इस क्षेत्र में खुद ब्रिटेन ही मुसीबत में है। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले तक रूस ही ब्रिटेन का सबसे बड़ा तेल सप्लायर था। दर्जनों प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप अब तक रूस का सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है। ऐसे में जॉनसन की ओर से यह मांग कि भारत तेल के लिए रूस पर निर्भरता कम करे, इसका उल्टा असर भी हो सकता है। माना जा रहा है कि जॉनसन इस मुद्दे पर सतर्कता के साथ उठाएंगे।